


भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण

EXTRAORDINARY

'भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]
No. 819]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2000/अग्रहायण 28, 1922
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2000/AGRAHAYANA 28, 1922

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2000

का.आ. 1131(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन.एस.सी.एन.) जिसमें इसके सभी गुट, स्कंध और अग्रिम संगठन शामिल हैं, को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन. जी. नन्दी की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 7/5/2000-एन.ई.-1]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2000

S.O. 1131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice N. G. Nandi, Judge of the Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) including all its factions, wings and front organisations as an unlawful associations.

[File No. 7/5/2000-NE. I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

